[2013] 2 एस.सी.आर. 1019

साहब हुसैन @साहब जान

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील सं. 2083-2084/2008)

18 अप्रैल, 2013

[पी. सदाशिवम और एम. वाई. इकबाल, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 – तीन लोगों सहित 5 हत्याओं का आरोपी – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अभिनिर्धारित – मृत्यु प्रकृति में, गवाहों के साक्ष्यों, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, अभियुक्त की फरारी, गिरफ़्तारी के समय उसका आचरण, प्रकटीकरण विवरण के अनुसार आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी, सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान, सभी उसे मानव वध अपराध से जोड़ते हैं और उसके अपराध को स्थापित करते हैं-उच्च न्यायालय का निर्णय दोषसिद्धि की पुष्टि करना और आगे के निर्देश के साथ मौत की सजा को 20 साल के कारावास में परिवर्तित करना कि अभियुक्त को इस बीच कोई छूट नहीं दी जाए, बरकरार रखा जाए-सजा/सजा-साक्ष्य-परिस्थितिजन्य साक्ष्य अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति।

दंड

आगे प्रतिबंध के साथ एक निश्चित अवधि के लिए सजा माफी-निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा पांच लोगों की मौत का दोषी पाया गया आरोपी तीन बच्चों सहित-उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आगे के निर्देश के साथ 20 साल की कैद तब तक कोई छूट नहीं दी जाएगी- आयोजितः उच्च न्यायालय के फैसले को कुएँ के प्रकाश में दोष नहीं दिया जा सकता है। एक दशक के दंड संहिता, 1860 पर उच्चतम न्यायालय के तर्कपूर्ण निर्णय – धारा 302।

अपीलार्थी पर तीन बच्चों सहित 5 व्यक्तियों की मौत के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 27-10-2006 पर 10.30 शाम को, पीडब्लू1 ने अपीलार्थी को पीडब्लू4 से बात करते हुए पाया कि उसने 'एस' पूरा कर लिया है। साली, तीन बच्चे और एक 'एमएम'। पीडब्लू1 उनके घर की ओर दौड़ा और एक तालाब में 'एमएम' पड़ा पाया। कमरे के बाहर खून और तीनों के शव बच्चों और 'एस' कमरों के अंदर लेटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि टेलीफोन पर नियोक्ता (पीडब्लू2)। इसके बाद, एक लिखित रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। एमएम 'भी रास्ते में है दोषसिद्धि, लेकिन सजा को 20 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया और आगे निर्देश दिया कि तब तक अभियुक्त को किसी भी लाभ का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने-

अभिनिर्धारित किया :

1.1. यह विवाद में नहीं है कि घटना में प्रश्न 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु कई चोटों के कारण हुई थी शरीर के विभिन्न अंग। यह भी विवाद में नहीं है कि घटना का कोई सीधा चश्मदीद गवाह नहीं है। यहां तक कि घटना के चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति, यदि विभिन्न परिस्थितियाँ साबित करती हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त था वीभत्स हत्याओं के लिए जिम्मेदार और शामिल, ऐसी परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 6] [1028-बी-डी]

1.2. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, उसमें उल्लिखित पूर्व-पोस्टमार्टम चोटें और डॉक्टरों के साक्ष्य से पता चलता है कि सभी पाँच मौतें प्रकृति में जानलेवा थीं। [पैरा 7] [1028-ई]

1.3. पीडब्लू 1 और 4 के संपूर्ण साक्ष्य, हालांकि उन्होंने घटना को नहीं देखा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, जिस तरीके से उन्होंने अदालत के सामने गवाही दी और उनके द्वारा बताए गए विवरण स्वीकार्य हैं और उसके बयान पर अविश्वास करने का कोई वैध कारण नहीं है। उनके साक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता-अभियुक्त वह व्यक्ति था जो घटना में शामिल था। [पैरा 9] [1029-सी]

1.4. अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, हालांकि एक कमजोर प्रकार साक्ष्य, दोषसिद्धि के लिए आधार बना सकता है यदिअभियुक्त द्वारा किया गया इकबालिया बयान स्वैच्छिक, सच्चा और सत्य है। भरोसेमंद और आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। अपीलार्थी अभियुक्त ने पीडब्लू-4 को घटना के विवरण का उल्लेख किया और निचली अदालतों ने उसके बयान को विश्वसनीय और विश्वसनीय स्वीकार किया।भरोसेमंद। पीडब्लू-4 का साक्ष्य विश्वसनीय, स्वीकार्य है और आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। यह द्वारा लिए गए रुख का समर्थन करता है पीडब्लू-1. यह भी अभिलेख में है कि पीडब्लू-4 अपीलार्थी का मित्र था और वे उसी क्षेत्र में रह रहे थे।उन परिस्थितियों में, द्वारा की गई पीडब्लू-4 के स्वीकारोक्ति के अपीलार्थी पर अन्य भौतिक साक्ष्य के साथ कार्रवाई की जा सकती है। [पैरा 10] [1029-डी-जी]

1.5. अपीलार्थी द्वारा प्रकटीकरण के आधार एक खून से सनी कुल्हाड़ी और उसके द्वारा पहने गए कपड़े पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की उपस्थिति में बरामद किए गए। इसके अलावा, खून से सनी चप्पल भी जब्त की गई। पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य को देखने पर नीचे की अदालतों ने पाया है कि वसूली स्वीकार्य और निष्कर्ष निकाला कि कोई कारण नहीं है उनके बयानों पर विश्वास न करें। [पैरा 11] [1029-एच; 1030-ए-सी]

1.6. यद्यपि अपीलार्थी का आचरण नहीं हो सकता है परिस्थितियों की श्रृंखला में मुख्य कड़ी उसे साबित करने के लिए अपराध, हालांकि, घटनास्थल से फरार होगा उसके अपराध को स्थापित करें और निर्दोषता की परिकल्पना को खारिज करें। यह सबूत से सामने आया है कि इसके तुरंत बाद घटना के बाद आरोपी गांव छोड़कर दिल्ली जाने वाली बस में सवार हो गया। लेकिन रास्ते में ही उन्हें पीडब्लू ने गिरफ्तार कर लिया। 16 2.20 बजे, 28.10.2006 पर। [पैरा 12] [1030-सी-डी]

1.7. अपीलार्थी द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, यहां तक कि धारा 313 के तहत भी उसके अचानक प्रस्थान के लिए बयान दिया गया है। दृश्य और दिल्ली जाना। किसी कारण के अभाव में, अपीलार्थी का आचरण अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है। इसके अलावा, जब अपीलार्थी से बस में पीडब्लू-16 द्वारा पूछताछ की गई, तो उसने अपना मूल नाम दबा दिया और कहा एक झूठा नाम और केवल आगे की पूछताछ पर, उसके मूल नाम का खुलासा किया। ये पहलू उसके आचरण के खिलाफ जाते हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। [पैरा 12-13][1030 - जी-एच; 1031-बी

1.8. उद्देश्य के संबंध में, पीडब्लू-1-सूचना देने वाले ने कहा कि अपीलार्थी का मृतक 'एस' के साथ झगड़ा हुआ था ईद का दिन। पीडब्लू-1 के इस कथन को पीडब्लू-4 के साक्ष्य से पुष्टि मिलती है।[पैरा14] [1031-सी-डी]

1.9. आगे एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट का मिलान हुआ मृतक के रक्त समूह और चप्पल, पैंट, शर्ट और कुल्हाड़ी पर पाए जाने वाले रक्त समूह के साथ। के रूप में नीचे दी गई अदालतों द्वारा सही निष्कर्ष निकाला गया है, रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती है। बयान में कहा गया अभियुक्त ने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया है, उसके पास न तो है इनकार किया और न ही दोषपूर्ण परिस्थितियों के बारे में बताया अभियोजन पक्ष पर भरोसा किया। [पैरा 15-16] [1031-E-G]

1.10. यह सच है कि अभियोजन पक्ष हो सकता है हालाँकि, विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, केवल एक व्यक्ति के कारण, मृतक के पति की जाँच की गई। जाँच नहीं की गई, अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 17] [1032-ए-बी]

1.11 . यह न्यायालय संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सभी परिस्थितियाँ विश्वसनीय, स्वीकार्य और विश्वसनीय हैं। अपीलार्थी-अभियुक्त को अपराध से जोड़ें और स्थापित करें उसका दोष। उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है। [पैरा 17] [1032-बी-सी]

2. इस अदालत ने कई मामलों में मौत को कम कर दिया है आजीवन कारावास की सजा जहाँ अपराध का आरोप लगाया गया हो

प्रकृति में गंभीर है, और जीवन प्रदान करते हुए कारावास, 20 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष के न्यूनतम कारावास को दोहराते हुए, यह उल्लेख करते हुए कि यदि उपयुक्त सरकार छूट देना चाहती है, तो इसकी अवधि समाप्त होने के बाद ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। अवधि ने कहा। तत्काल मामले में तथ्यों पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया कुछ प्रतिबंधों को लागू करने वाला कारावास, इसका निर्णय अच्छी तरह से तर्क के साथ और प्रकाश में दोष नहीं दिया जा सकता है एक दशक से अधिक के निर्णय, इस न्यायालय ने बरकरार रखा उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया जिसमें शामिल हैं उसमें बताए गए कारण। [पैरा 29 और 31] [1036-बी-सी; 1043 एच; 1044-ए-बी]

श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य 2001 (3) एससीआर 656 = (2001) 6 एस. सी. सी. 296; प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम संदीप @ बबलू प्रकाश खैरनार (पाटिल) 2001 (5) पूरक। एस. सी. आर. 612 = (2002) 2 एस. सी. सी. 35; राम अनूप सिंह और अन्य। बनाम। बिहार राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 686; नजीर खान और अन्य। बनाम। दिल्ली राज्य 2003 (2) पूरक। एससीआर 884 = (2003) 8 एससीसी 461; स्वामी श्रद्धानंद (2) मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य, 2008 (11) एससीआर 93 = (2008) 13 एससीसी 767; हारु घोष बनाम पश्चिम

बंगाल राज्य 2009 (13) एस. सी. आर. 847 = (2009) 15 एस. सी. सी. 551; रामराज नन्हू बिह्न बनाम राज्य छत्तीसगढ़ 2009 (16) एस. सी. आर. 367 = (2010) 1 एस. सी. सी. 573; नील कुमार अनिल कुमार बनाम। हरियाणा राज्य 2012 (5) एससीआर 696 = (2012) 5 एससीसी 766; संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 (5) एस. सी. आर. 952 = (2012) 6 एस. सी. सी. 107; गुरवेल सिंह गाला और अन्र। बनाम पंजाब राज्य (2013) 2 एससीसी 713; जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एस. सी. सी. 20; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684-पर भरोसा किया।

संगीत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2013) 2 एससीसी 452-अप्रयोज्य रखा गया।

मामला कानून संदर्भः

2001 (3) एससीआर 656 पैरा 19

2001 (5) पूरक एस. सी. आर. 612 पर निर्भर पैरा 20

(2002) 6 एस. सी. सी. 686 पैरा 21

2003 (2) पूरक। एस. सी. आर. 884 पर निर्भर पैरा 22

2008 (11) एससीआर 930 पैरा 23

2009 (13) एससीआर 847 पैरा 24

2009 (16) एससीआर 367 पैरा 25

2012 (5) एससीआर 696 पैरा 26

2012 (5) एससीआर 952 पैरा 27

(2013) 2 एस. सी. सी. 713 पैरा 28

(2013) 2 एससीसी 452 पैरा 29

1973 (2) एससीआर 541 पैरा 30

1980 (2) एस. सी. सी. 684 पैरा 30

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2083-2084/2008 ।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपराधिक अपील संख्या ९१/2008 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.03.2008 से उत्पन्न।

पीयूष के. रॉय, काकली रॉय, अपीलार्थी के लिए ।

अर्चना पाठक दवे, डॉ. सुमंत भारद्वाज, अंकिता चौधरी, मृदुला रे, मिलिंद कुमार, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

पी. सतशिवम, न्यायाधिपति.

1. इन अपीलों को निर्देशित किया जाता है जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.03.2008 के विरुद्ध 2007 का आपराधिक मृत्यु संदर्भ संख्या 1 और आपराधिक अपील नं. 91 और 2008 का 92 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश और दिनांक 13.12.2007 की सजा के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), सीरियल नंबर 1, जयपुर, जिला जयपुर (राजस्थान) ने मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।

2. संक्षिप्त तथ्यः

(क) यह पाँच व्यक्तियों की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारती कॉलोनी, कुंडा, तहसील आमेर, जिले में रह रहे थे। जयपुर, राजस्थान।

(ख) 27.10.2006 पर, 10.30 शाम को, एक जफर (पीडब्लू-1)-सूचना देने वाला, जो उपरोक्त स्थान पर भी रह रहा था, घर वापस जाते समय उसने अपीलार्थी को यहाँ एक व्यक्ति से बात करते हुए पाया। सतीश (पीडब्लू-4) ने कहा कि उन्होंने सीमा भाबी (बहन-इन) को समाप्त कर दिया था। कानून) और तीन बच्चों और मुन्ना मवाली को भी मार डाला। यह सुनकर पीडब्लू-1 उनके घर की ओर गया और पाया कि मुन्ना मवाली अपने कमरे के बाहर चाबुत्रा पर खून से लथपथ पड़ा था और उसका भतीजा कालू अंदर मृत पड़ा था। कमरे में मुन्ना की पत्नी सीमा, लालू

चाचा के बेटे ईशा और मुन्ना के बेटे सोनू के शव तालाब में पड़े हुए थे। दूसरे कमरे में खून। यह देख वह भाग गया। सतीश (पीडब्लू-4) ने उनसे अपीलार्थी के बारे में पूछा। पीडब्लू 4 ने उसे सूचित किया कि वह सड़क बदलने के बाद राजमार्ग की ओर भागा कपड़े। इसके बाद पीडब्लू-1 ने बल्लू भाई को इसकी सूचना दी। बल्लू (पीडब्लू-2) दूरभाष पर। कुछ समय बाद, एक लिखित रिपोर्ट एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन, आमेर को सौंपी गई। पीडब्लू-1 द्वारा, सुबह 12.30 मुन्ना मवाली को हटा दिया गया था पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

(ग) उक्त जानकारी के आधार पर, एक मामला अपराध है। 1860 ('आई. पी. सी.) साहिब हुसैन के खिलाफ दर्ज किया गया था। शवों का पोस्टमार्टम भी किया गया। इसके बाद जाँच dk आरोप पत्र दाखिल कयलाक बाद मामला दर्ज कयल गेल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) के न्यायालय में, क्रमिक 1026 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 2 एस सी आर। संख्या 1, जयपुर, जिला जयपुर (राजस्थान) और सत्र मामला संख्या 90/2006 के रूप में क्रमांकित। मुकदमे के दौरान अदालत को पता चला कि दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। अपीलार्थी और सीमा (मृतक होने के कारण) ने ईद के दिन ऐसा वीभत्स कृत्य किया। हालांकि, लेना

(घ) उक्त आदेश से व्यथित, अपीलार्थी-अभियुक्त ने आपराधिक अपील संख्या को प्राथमिकता दी। 91 और 92/2008 उच्च न्यायालय के समक्ष। 2007 का मृत्यु संदर्भ संख्या 1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के तहत को भी निचली अदालत ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए प्राथमिकता दी थी। विवादित निर्णय द्वारा दिनांक 05.03.2008, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों का निपटारा मौत की सजा को कम करके किया आजीवन कारावास और यह भी निर्देश दिया कि वह गुजर चुका है और उसे किसी भी छूट का लाभ भी नहीं मिलेगा किसी भी शुभ अवसर पर राज्य द्वारा या भारत सरकार द्वारा।

(ङ) उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से जेल से इन अपीलों को प्राथमिकता दी।

3. सुना श्री पीयूष के. रॉय, अपीलार्थी-अभियुक्त के लिए विद्वान न्याय मित्र और सुश्री अर्चना पाठक दवे, विद्वान राजस्थान राज्य के लिए वकील।

तर्कः

4. (क) विद्वान न्यायमित्र श्री पीयूष के. रॉय ने हमें पूरी सामग्री के माध्यम से ले जाने के बाद प्रस्तुत किया कि कोई प्रत्यक्ष नहीं है

घटना और अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में बोलने के लिए चश्मदीद गवाह पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। उनके अनुसार, परिस्थितियों पर निर्भर अभियोजन संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं किया गया है और किसी भी मामले में, परिस्थितियों को स्थापित किया गया है।अपीलार्थी के खिलाफ अपीलार्थी के खिलाफ अपराध को घर लाने के लिए एक पूरी श्रृंखला प्रदान न करें। उन्होंने आगे कहा कि एफ. आई. आर. अपने आप में संदिग्ध है, उस स्थान के संबंध में विरोधाभास हैं जहाँ अभियुक्त ने सबसे पहले खुलासा किया है सतीश (पीडब्लू-4) की घटना, में कई दुर्बलताएँ इस तथ्य के संबंध में गवाहों के बयान कि घटना कई घरों से घिरी हुई थी, कोई विश्वसनीय नहीं अभियोजन पक्ष की ओर से व्यक्ति से पूछताछ की गई और हथियार (कुल्हाड़ी), कपड़े, चप्पल आदि की बरामदगी संदिग्ध होने के कारण, उन्होंने अपीलार्थी को बरी करने के लिए प्रार्थना की अभियुक्त। वैकल्पिक रूप से, श्री रॉय ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 20 वर्ष पूरे होने से पहले सरकार द्वारा माफी के अधिकार को छीनने का आदेश पारित करना उचित नहीं था। कारावास की सजा।

(4)(ख) दूसरी ओर, सुश्री अर्चना पाठक दवे, राज्य के लिए विद्वान वकील, हमें सभी के माध्यम से ले जाने के बाद प्रस्तुत सामग्री कि अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से स्थापित किया है विभिन्न परिस्थितियाँ जो अपराध के बारे में बात करती हैं अपीलार्थी, जिसमें बरामदगी, अतिरिक्त

न्यायिक कबुलीजबाब, अपीलार्थी का आचरण, जिसके समय झूठे नाम का उल्लेख किया गया हो, उसकी गिरफ्तारी आदि। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई इनकार नहीं है संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान कि वह था घटना स्थल से फरार जब तक कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और उसी के संबंध में पीडब्लू 1 और 4 के सबूत हैं. निरंतर और विश्वसनीय भी। सुश्री अर्चना ने यह भी कहा कि इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अपीलार्थी 5 व्यक्तियों की मौत का कारण बना और उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को कम कर दिया है इसके पहले के विभिन्न निर्णयों के आधार पर आजीवन कारावास न्यायालय, उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाने में न्यायसंगत ठहराया 20 वर्ष पूरे होने से पहले छूट प्रदान करना कारावास।

5. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मौखिक और वृत्तचित्र सहित सभी सामग्रियों का अध्ययन किया सबूत।

6. यह विवाद में नहीं है कि विचाराधीन घटना में 5 व्यक्ति, अर्थात्। , सीमा, मुन्ना मवाली, कालू, ईशा और सोनू की मृत्यु हो गई। और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौतों के कारण थे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई चोटें। यह भी विवाद में नहीं है कि इस घटना का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं है। यह 10.30 दोपहर के आसपास, 27.10.2006 पर हुआ। घटना के चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति में भी, यदि विभिन्न परिस्थितियाँ साबित करती हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त था

जिम्मेदार और वीभत्स हत्याओं में शामिल, निर्णय ऐसी परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, हमें देखना होगा कि क्या परिस्थितियां अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा पूरी तरह से स्थापित किया गया है या नहीं?

7. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पूर्व पोस्टमॉर्टम चोटों का उल्लेख किया गया उसमें और संबंधित डॉक्टरों के साक्ष्य से पता चलता है कि सभी पाँच मौतें हत्या की प्रकृति की थीं। चूंकि उपरोक्त पहलू गंभीर रूप से विवादित नहीं है, प्रकृति को संदर्भित करने का कोई कारण नहीं है चोटों और डॉक्टर की अंतिम राय जिसने पोस्टमॉर्टम संचालन किया ।

8. अभियोजन पक्ष ने जाफर के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया (पीडब्लू-1) और सतीश (पीडब्लू-4)। पीडब्लू-1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि , कि वह भारती कॉलोनी में एक बल्लू भाई के साथ रहता था कुंडा, आमेर। उनके अनुसार, बल्लू भाई के पास कई हाथी थे। और वह अपने एक हाथी की सवारी करते थे। मुन्ना और मुन्ना मवाली (मृतक होने के बाद से) भी हाथी सवार थे। वह उन्होंने आगे बताया कि घटना के दिन, लगभग दोपहर 1 बजे, जब वह अपने घर जा रहे थे, उन्होंने अपीलार्थी-आरोपी को सतीश (पीडब्लू-4) से बात करते हुए देखा कि उसने सीमा भाबाई, मुन्ना मावलाई और तीन बच्चों की हत्या कर दी। यह सुनकर वह तुरंत उनके पास गया। घर में देखा कि मुन्ना मवाली अपने कमरे के बाहर खून से लथपथ पड़ा था और कमरों के अंदर, सीमा और तीन बच्चे मृत

पड़े थे। पीडब्लू-1 के साक्ष्य के अलावा, एक सतीश, जिसकी पीडब्लू-4 के रूप में जांच की गई थी, ने इसका समर्थन किया जाफर की गवाही (पीडब्लू-1)। अपने साक्ष्य में, उन्होंने समझाया कि वह एक हाथी सवार थे और बल्लू भाई के हाथी की सवारी करते थे और उपरोक्त स्थान पर रहते थे। उन्होंने आगे कहा कि कहा कि लगभग 10.30 शाम को, अपीलार्थी-अभियुक्त आया उसे घटना के बारे में बताया।

9. पीडब्लू 1 और 4 के पूरे साक्ष्य का अवलोकन, हालांकि उन्होंने उस घटना को नहीं देखा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया था, जिस तरह से उन्होंने न्यायालय के समक्ष गवाही दी थी और उनके द्वारा बताए गए विवरण स्वीकार्य हैं और कोई नहीं है उनके बयानों पर अविश्वास करने का वैध कारण। उनका साक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त वह व्यक्ति था घटना में कौन शामिल था।

10. अभियोजन पक्ष अतिरिक्त न्यायिक पर बहुत अधिक निर्भर था स्वीकारोक्ति। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, हालांकि एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य, दोषसिद्धि का आधार बन सकता है यदि स्वीकारोक्ति अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य स्वैच्छिक, सच्चा और भरोसेमंद है। दूसरे शब्दों में, यदि यह आत्मविश्वास को प्रेरित करता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उल्लेख किया है कि सतीश (पीडब्लू-4) और अदालतों को घटना का

विवरण उन्होंने अपने संस्करण को विश्वसनीय और भरोसेमंद के रूप में स्वीकार किया। सुश्री अर्चना, राज्य के लिए विद्वान वकील ने हमें पूरे दौर में ले जाया सतीश (पीडब्लू-4) का साक्ष्य और उसी से गुजरने पर, हम संतुष्ट हैं कि उनका साक्ष्य विश्वसनीय, स्वीकार्य और यह हमारे आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि+ पीडब्लू-4 का साक्ष्य पीडब्लू-1 द्वारा लिए गए रुख का समर्थन करता है। यह भी है अभिलेख पर कि पीडब्लू-4 अपीलार्थी-अभियुक्त का मित्र था और वे एक ही क्षेत्र में रह रहे थे। इनमें परिस्थितियों, अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू को दी गई स्वीकारोक्ति-4 अन्य भौतिक साक्ष्य के साथ कार्रवाई की जा सकती है।

11. आइए हम उन वसूली पर विचार करें जिन पर हम भरोसा करते हैं अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को साबित करने के लिए। यह है मामला अभियोजन कि अपीलार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था 28.10.2006 , उनके प्रकटीकरण के आधार पर 1030 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 2 एस. सी. आर. बयान, एक खून से सना कुल्हाड़ी बरामद हुई ज्ञापन (Exh. पी-10) और उनके द्वारा पहने गए कपड़े, जो थे एक कमरे में छिपाकर, रिकवरी मेमो (एक्सएच) के माध्यम से बरामद किया गया। पी-11) मोहम्मद की उपस्थिति में। सलीम बल्लू (पीडब्लू-2) और पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य के माध्यम से, नीचे दी गई दोनों

अदालतों ने पाया कि वसूली स्वीकार्य है और निष्कर्ष निकाला है कि वहाँ है उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अपीलार्थी-अभियुक्त का आचरण है। हालांकि यह नहीं हो सकता है अपराध साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक मुख्य कड़ी अपीलार्थी-अभियुक्त, हालाँकि, घटनास्थल से फरार है अभियुक्त के अपराध को स्थापित करेगा और निर्दोषता की परिकल्पना को खारिज कर देगा। हाथ पर मामले में, यह से बाहर आया है सबूत है कि घटना के तुरंत बाद, वह गाँव छोड़ कर चला गया रोजनामचा में जानकारी (पी-51)। उनके अनुसार, लगभग 2.20 बजे उन्होंने शाहजहांपुर बैरियर पर एक बस रोकी। जो जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और अपीलार्थी उस बस में बैठा था। जब उसने अपीलार्थी से उसकी पहचान के बारे में पूछा, तो शुरू में उसने अपना नाम ज़ाकिर हुसैन बताया, लेकिन कब वह घबरा गया, इससे उसके मन में संदेह पैदा हो गया। पूछताछ करने पर उसने अपना सही नाम साहिब हुसैन बताया और उसके बाद उसे आमेर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा भी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। घटनास्थल से अचानक प्रस्थान करने और दिल्ली जाने के लिए धारा 313 के तहत बयान। किसी कारण के अभाव में, अपीलार्थी का आचरण अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है।

13. एक अन्य पहलू जो अपीलार्थी के आचरण के खिलाफ जाता है जो पहले के पैराग्राफ से संबंधित है, वह यह है कि जब वह दिल्ली जा रही बस में पीडब्लू-16 द्वारा पूछताछ की गई थी जयपुर से, उन्होंने अपना मूल नाम gVk दिया और अपना नाम जाकिर हुसैन के रूप में नाम crk;k केवल आगे की पूछताछ पर, वह उन्होंने अपने मूल नाम का खुलासा किया। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया है, उसे दबाने का कोई कारण नहीं था मूल नाम और पी. डब्ल्यू.-16 को गलत नाम दें। ये पहलू उसके आचरण के खिलाफ जाएँ और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करें।

14. उद्देश्य के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने इस पर भरोसा किया जाफर (पीडब्लू-1) का साक्ष्य-सूचना देने वाला, जो अपीलार्थी के पास था ईद के दिन सीमा (मृतक) के साथ झगड़ा। द. जाफर (पीडब्लू-1) के उपरोक्त कथन को पुष्टि मिलती है सतीश (पीडब्लू-4) का साक्ष्य जिसने न्यायालय के समक्ष गवाही दी कि ईद के दिन मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और आरोपी। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया है, उपरोक्त घटना को देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है तथ्य यह है कि जब अपीलकर्ता सीमा, मुन्ना मवाली, कालू, ईशा और सोनू के व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुंचे लेकिन उन्हें भी मार दिया गया।

15. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो समर्थन करता है अभियोजन सिद्धांत एफ. एस. एल. रिपोर्ट और डी. एन. ए. रिपोर्ट है जो मृतक के रक्त समूह और रक्त के साथ मेल खाता है चप्पल, पैंट, कमीज और कुल्हाड़ी पर पाया जाने वाला समूह। के अनुसार हम, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा सही निष्कर्ष निकाला गया है, उपरोक्त रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करें।

16. इसके अलावा, हमने बयान को भी सत्यापित किया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्तों में से जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी ने न तो इनकार किया है और न ही इसके बारे में कहा है अभियोजन पक्ष द्वारा दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों पर भरोसा किया गया।

17. हालाँकि अपीलार्थी अभियुक्त के विद्वान वकील श्री रॉय ने कहा है कि एफ़. आई. आर. अपने आप में संदिग्ध है। उसी के माध्यम से, द्वारा निर्भर अन्य सामग्रियों के साथ अभियोजन पक्ष, हम संतुष्ट हैं कि प्राथमिकी जानबूझकर 1032 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 2 एस. सी. आर. नहीं थी। अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया। अपीलार्थी के लिए सीखा हुआ वकील यह भी बताया गया है कि मृतक सीमा के पति मुन्ना की गैर-जांच, मामले के लिए घातक है अभियोजन। यह सच है कि अभियोजन पक्ष जांच कर सकता था हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि केवल एक कारण सेव्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला

बाहर नहीं फेंका जा सकता। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे विश्वसनीय, स्वीकार्य और विश्वसनीय हैं।अपीलार्थी-अभियुक्त को विचाराधीन अपराध के संबंध में जोड़ें। हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा।

18. वैकल्पिक तर्क के बारे में, अर्थात। , कि उच्च न्यायालय का निर्देश कि अपीलार्थी नहीं होगा जेल से तब तक रिहा किया जाता है जब तक कि वह 20 साल की जेल की सजा काट चुका हो, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जो वह पहले ही बिता चुका है। और किसी भी शुभ अवसर पर राज्य या भारत सरकार से किसी भी छूट के लाभ का हकदार नहीं है। क्या अदालतों को किसी भी कारण से संहिता के तहत छूट की शक्ति को सीमित करने की आवश्यकता है?

19. श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 296 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

> "24. इसलिए, न्याय के हित में, हम कम्यूट करते है अपीलार्थी पर अधिरोपित मृत्युदंड और प्रत्यक्ष कि अपीलार्थी की सजा होगी - आजीवन कारावास। हम आगे निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम 20 साल का कारावास नहीं बिताया हो। अपीलार्थी द्वारा पहले से गुजर चुकी अवधि।"

20. प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम राज्य महाराष्ट्र राज्य बनाम संदीप @ बबलू प्रकाश खैरनार (पाटिल) (2002) 2 एस. सी. सी. 35, यह न्यायालय निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

> "24 ..... इस मामले में भी, तथ्यों पर विचार करते हुए और परिस्थितियों में, हम मौत की सजा को दरकिनार करते हैं और निर्देश दें कि उसके द्वारा की गई हत्याओं के लिए, वह सेवा करेगा अवधि सहित कम से कम 20 वर्ष का कारावास पहले से ही उससे गुजर चुका है।"

21. राम अनूप सिंह और ओआरएस में बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 686, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

> "27 ..... इसलिए, सभी पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर प्रासंगिक परिस्थितियों में हमारा विचार है कि इस मामले में मौत की सजा की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए, द्वारा दी गई मौत की सजा को दरकिनार कर दें ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को पुष्टि ललन सिंह और बब्बन सिंह। हम इसके बजाय वाक्य देते हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी शर्त है कि

उन्हें पूरा करने से पहले रिहा नहीं किया जाएगा उनसे गुज़ारा "।

22. नजीर खान और ओरस में। बनाम दिल्ली राज्य (2003) 8 एस. सी. सी. 461, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

"44 ..... अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए और कृत्यों और परिणामों की कायरतापूर्ण प्रकृति बाहर उड़ गया और, जीवन के सम्मान में उड़ गया होगा सजा, 20 साल की अवधि के लिए कारावास उचित रहें। अभियुक्त अपीलार्थी नहीं होंगे 20 की पूर्वोक्त अवधि से किसी भी छूट का हकदार बरसों "।

23. स्वामी श्रद्धानंद में (2) @मुरली मनोहर इस पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तार से विचार किया है। न्यायालय जिसे हम अपने आदेश के बाद के भाग में संदर्भित करने जा रहे हैं

24. हारू घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2009) 15 सी 551, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"43. यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है कि क्या सजा दी जानी चाहिए। आम तौर पर, यह होगा आजीवन कारावास। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपीलार्थी/अभियुक्त को दंड, क्योंकि वह पहले से ही आजीवन कारावास की सजा की

छाया में है, हालाँकि उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। के तहत परिस्थितियों में, हमारी राय में, स्वामी के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया मार्ग अपनाना बेहतर होगा। श्रद्धानंद (ऊपर उद्धृत), जहाँ न्यायालय ने एक ओर से मृत्युदंड और एक ओर से मृत्युदंड के बीच के अंतराल का उल्लेख किया है। आजीवन कारावास, जो वास्तव में 14 साल तक आ सकता है ' कारावास। उस मामले में, न्यायालय ने कहा किमामला हो सकता है।

44. हम अपीलार्थी/अभियुक्त को भेजने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। उसका शेष जीवन; हालाँकि, हम देखते हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त के मामले में आजीवन कारावास नहीं होगा वास्तविक कारावास की सजा के 35 वर्ष से कम, जिसका अर्थ है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को जेल में रहना होगा। न्यूनतम 35 वर्ष।

45. इस अवलोकन के साथ, अपील का निपटारा किया जाता है, हालाँकि, मौत की सजा की पुष्टि नहीं हुई है और इसके बजाय, उस वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो हमारे पास है इंगित किया "।

25. रामराज नन्हू बिह्नू बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ (2010) 1 एस. सी. सी. 573, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया,

> "25. वर्तमान मामले में, तथ्य ऐसे हैं कि याचिकाकर्ता भाग्यशाली है कि वह मौत की सजा से बच गया है। हमे नहीं लगता कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ याचिकाकर्ता 14 वर्ष 1035 के पूरा होने पर जारी किया जाना चाहिए। कारावास। समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता का मामला संबंधित अधिकारियों द्वारा उसके बाद लिया जा सकता है छूट सहित 20 साल का कारावास पूरा किया अर्जित किया। "

26. नील कुमार अनिल कुमार बनामहरियाणा राज्य 5 एस. सी. सी. 766, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "39. इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम मृत्युदंड को दरकिनार करें और आजीवन कारावास की सजा दें।अपीलार्थी को कम से कम 30 साल की जेल की सजा काटनी होगी। क्षमा किए बिना, उसके मामले पर विचार करने से पहले पूर्व-परिपक्व रिलीज "।

27. संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 107 में, यहआई. आर. टी. निम्नलिखित रूप में देखा गयाः " 75. उपरोक्त

निर्णय को ध्यान में रखना और इसमें शामिल होना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मृत्युदंड का अधिरोपण हम मानते हैं कि आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल की जेल की सजा काटें। समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले पर विचार करने से पहले।

28. गुरवेल सिंह @गाला और अन्र के मामले में। बनाम राज्यपंजाब (2013) 2 एस. सी. सी. 713, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

> "20 ..... तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना। इस मामले में हम मानते हैं कि मृत्युदंड का अधिरोपणअपीलार्थियों को वारंट नहीं दिया गया था, लेकिन जीवन प्रदान करते समय अपीलार्थियों को कारावास, हम मानते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए बिना किसी छूट के कम से कम तीस साल जेल की सजा काटें। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा और द्वारा पुष्टि की गई उच्च न्यायालय को ऊपर के रूप में संशोधित किया गया है। इसके तहत परिस्थिति, हम सजा को मौत से बदलकर जीवन में बदल देते हैं कारावास। इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करना संदीप (ऊपर) में अदालत का विचार है कि 1036 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 2

एस. सी. आर. तीस साल की न्यूनतम सजा पर्याप्त होगी।

दण्ड, जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है।

29. यह स्पष्ट है कि एक दशक से अधिक समय से, कई में मामले, जब भी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया हो कारावास जहाँ कथित अपराध गंभीर प्रकृति का है,आजीवन कारावास का आदेश देते समय, इस न्यायालय ने 20 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष के न्यूनतम कारावास को दोहराया, जिसका उल्लेख करते हुए, यदि उपयुक्त सरकार माफी देना चाहते हैं, उसी पर विचार करना होगा उक्त अवधि की समाप्ति के बाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त पहलू संगीत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 452 के मामले में इस न्यायालय द्वारा सहमत नहीं था, जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

"54. इसके द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ निर्णयों को पढ़ें। 20 वर्ष, 25 वर्ष और कुछ मामलों में बिना किसी छूट के सजा देना। क्या इसकी अनुमति है? क्या यह हो सकता है? न्यायालय (या उस मामले के लिए कोई भी न्यायालय) उपयुक्त को रोकता है किसी दोषी को सजा में छूट देने से सरकार? इस अदालत ने स्वामी में क्या किया है?श्रद्धानंद और कई अन्य मामलों में 20 साल या 30 साल के मृत्युदंड के अपराध में सजा छूट के बिना कारावास, प्रभावी रूप से निषेध करने के लिए है अपनी शक्ति का प्रयोग करने से उपयुक्त सरकार निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट। हमारी

राय में, यह मुद्दा आगे और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हमारी राय है कि इसकी अनुमति नहीं है। उपयुक्त सरकार को यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी सजा में छूट, चाहे जो भी कारण हो।"

इस मामले में, हालांकि डिवीजन बेंच ने संदेह जताया स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के बारे में, फिर भी इसे वृहत पीठ को संदर्भित नहीं किया गया है। स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में, लेने के बाद ठीक उसी तरह, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सभी प्रासंगिक बातों का विश्लेषण किया। पहले के निर्णयों सहित पहलुओं पर चर्चा की गई निम्नलिखित परिच्छेदः

> "88. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक और बिहार दोनों में आजीवन कारावास के दोषियों को धर्म परिवर्तन द्वारा छूट दी जाती है 20 वर्ष की निश्चित अवधि में आजीवन कारावास। आजीवन कारावास को एक निश्चित कारावास में परिवर्तित माना जाना राज्य सरकारों द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों द्वारा कार्यकाल स्पष्ट रूप से निर्णयों की एक लंबी कतार के सामने उड़ता है इस न्यायालय और हमें डर है कि कानून का कोई प्रावधान नहीं था इस तरह के पाठ्यक्रम को मंजूरी देने के लिए हमारे ध्यान में लाया गया। यह इस प्रकार है यह देखने के लिए कि आजीवन

कैदियों को माफी दी जाती है और चौदह साल की सजा पूरी करने पर जेल से रिहा बिना किसी ठोस कानूनी आधार के। कोई सुरक्षित रूप से यह मान सकता है कि अन्य राज्यों में स्थिति बेहतर नहीं होगी। यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान भी ले सकता है कि छूट सबसे यांत्रिक तरीके से आजीवन कैदियों को अनुमति दी जाती है किसी भी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बिना दोषी और प्रभाव के रूप में किसी भी उचित मूल्यांकन के बिना समाज में किसी विशेष दोषी की शीघ्र रिहाई। छूट का अनुदान नियम है और छूट से इनकार किया जाता है,कोई कह सकता है, दुर्लभतम मामलों में। 89. यहाँ, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह स्थिति रही है बहुत लंबे समय तक। 1973 में जगमोहन में सिंह ने इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित अवलोकनः

"14. ..... हमारे आपराधिक कानून के संदर्भ में जो दंडित करता है हत्या, कोई इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आजीवन कारावास ज्यादातर मामलों में एक दर्जन साल तक की जेल हो जाती है और यह गंभीरता से सवाल किया जा सकता है कि क्या वह एकमात्र वैकल्पिक

मृत्यु के लिए एक पर्याप्त विकल्प होगा दंड "। (जोर दिया गया)

जगमोहन के पांच साल बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 433-ए को शामिल किया गया था। _____

"156. यह स्मरणीय है कि जगमोहन में इस न्यायालय ने यह देखा गया कि व्यवहार में आजीवन कारावास की राशि 12 है। वर्षों तक जेल में। अब, धारा 433-ए शक्ति को प्रतिबंधित करती है। को दी गई छूट और परिवर्त्तन धारा 432 और 433 के तहत उपयुक्त सरकार, इसलिए कि एक व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है या जिसकी मौत की सजा को कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है आजीवन कारावास की सजा कम से कम 14 साल की होनी चाहिए।इस प्रकार धारा 433-ए द्वारा जो कुछ भी बदला गया है, वह यह है कि इसे शामिल करने से पहले अधिकांश मामलों में आजीवन कारावास एक दर्जन वर्ष के कारावास और उसके बाद परिचय यह चौदह साल के कारावास तक काम करता है।लेकिन जगमोहन में यह अवलोकन कि ऐसा नहीं हो सकता है मृत्युदंड के पर्याप्त विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया यह अभी भी सच है।

90. इससे पहले इस फैसले में यह उल्लेख किया गया था कि श्री भगवान के फैसले में वैधता पर उपयोगी चर्चा की गई है। आजीवन कारावास के दोषियों के मामले में माफी। फैसले में श्री भगवान, पहले के संदर्भ और उद्धरण देते हैं एम. पी. बनाम राज्य में निर्णय रतन सिंह जो बदले में संविधान पीठ के फैसले के एक अंश का हवाला देते हैं गोपाल विनायक गोडसे। रतन सिंह के उद्धरण को यहाँ पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगाः " 4. जहाँ तक पहले बिंदु का संबंध है, अर्थात्, कि कैदी कर सकता है 20 वर्ष की समाप्ति पर स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा पंजाब जेल नियमावली या इसके तहत बनाए गए नियम कारागार अधिनियम, मामला अब एकीकृत नहीं है। गोपाल विनायक में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया गोडसे वी. महाराष्ट्र राज्य, जहाँ न्यायालय निम्नलिखित पंडित किशोरी लाल बनाम में प्रिवी काउंसल का निर्णय। राजा सम्राट ने इस प्रकार कहाः

4. ..... उस धारा के तहत एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए ले जाया गया या उक्त धारा के अधिनियमन से पहले कोई अन्य शर्तें कठोर सजा पाने वाले व्यक्ति के रूप में

व्यवहार किया जाएगा आजीवन कारावास या उक्त अवधि के लिए कारावास।

5. अगर ऐसा है तो अगला सवाल यह है कि क्या कोई प्रावधान है। कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा, उचित सरकार द्वारा किसी भी औपचारिक छूट के बिना एक निश्चित अवधि के लिए स्वचालित रूप से एक के रूप में माना जा सकता है।दंड संहिता की संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया है।दंड प्रक्रिया या कारागार अधिनियम। ..... आजीवन कारावास या आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। दोषी व्यक्ति की पूरी शेष अवधि के लिए परिवहन या कारावास के रूप में माना जाएगा। प्राकृतिक जीवन '।

न्यायालय ने आगे कहाः

'7. ..... लेकिन जेल अधिनियम किसी को भी अधिकार प्रदान नहीं करता है सजा को कम करने या माफ करने की शक्ति; यह केवल जेलों के विनियमन और उनके उपचार के लिए प्रदान करता है। कैदियों को उसमें बंद कर दिया गया। कारागार अधिनियम की धारा 59 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है,अन्य बातों के साथ-साथ

अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार के लिए। इसलिए, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का अर्थ इसके भीतर लगाया जाना चाहिए -अधिनियम के दायरे का दायरा। ..... उक्त नियमों के तहत धारा 401, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक उपयुक्त सरकार का आदेश, रिहाई के लिए एक पूर्व शर्त है। कोई अन्य नियम हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जो प्रदान करता है सजा पाए कैदी पर एक अक्षम्य अधिकार जीवन के लिए बिना शर्त रिहाई के लिए परिवहन छूट सहित किसी विशेष अवधि की समाप्ति।नियम + 0 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2013] 2 एस सी आर। जेल अधिनियम के तहत कम सजा का स्थान न लें जीवन के लिए परिवहन की सजा के लिए।

8. ..... माफी का सवाल विशेष रूप से उपयुक्त सरकार के प्रांत के भीतर है; और इस मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि यद्यपि उपयुक्त सरकार ने संहिता की धारा 401 के तहत कुछ छूट दी थी दंड प्रक्रिया में, इसने पूरी सजा को माफ नहीं किया। इसलिए हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता को अभी तक रिहा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि जेल अधिनियम या जेल के तहत बनाए गए नियम मैनुअल कैदी

की कुल अवधि को प्रभावित नहीं करता है। पीड़ित होना लेकिन केवल प्रशासनिक निर्देशों के बराबर है समय-समय पर नियमों के अनुसार कैदी को दी जाने वाली विभिन्न छूटों के संबंध में। यह न्यायालय ने आगे बताया कि छूट का प्रश्न पूरा वाक्य या इसका एक हिस्सा धारा 401 के तहत उपयुक्त सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। दंड प्रक्रिया संहिता और न ही धारा 57 दंड संहिता और न ही कोई नियम या स्थानीय अधिनियम द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दंड संहिता के तहत अदालत। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि आजीवन कारावास तब तक सुनिश्चित करेगा जब तक कि अभियुक्त का जीवनकाल क्योंकि कैदी की मृत्यु और दी गई छूट की एक विशेष अवधि तय करना संभव नहीं है। नियमों के तहत इसे आजीवन कारावास की सजा के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है।(जोर दिया गया) इसके अलावा, पैरा 23 में, श्री भगवान में निर्णय निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 23. मारू राम बनाम। भारत संघ इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने उपरोक्त स्थिति को दोहराया और यह देखा

गया कि अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि साहिब हुसैन साहिब जान बनाम 1041 का राज्य राजस्थान [पी. सतशिवम, जे.]धारा 433-ए हम केवल आजीवन कारावास से निपटते हैं, छूट कहीं नहीं ले जाती है और एक कैदी को रिहा करने का अधिकार नहीं दे सकती है। इसके अलावा, लक्ष्मण नस्कर बनाम। डब्ल्यू. बी. की स्थिति, संदर्भित करने के बाद गोपाल विनायक गोडसे बनाम के निर्णय पर। महाराष्ट्र राज्य, न्यायालय ने उस सजा को दोहराया ' आम तौर पर 'आजीवन कारावास' का अर्थ है कारावास दोषी व्यक्ति की पूरी शेष अवधि प्राकृतिक जीवन; कि इस तरह की सजा से गुजर रहा एक दोषी जेल के तहत सजा के अपने हिस्से की छूट अर्जित कर सकता है नियम लेकिन एक आदेश के अभाव में इस तरह के छूट एक उपयुक्त सरकार जो पूरी शेष राशि का भुगतान करती है इस धारा के तहत उसकी सजा दोषी को पूर्ण आजीवन कारावास से पहले स्वचालित रूप से रिहा होने का अधिकार नहीं देती है यदि सेवा की। यह देखा गया कि हालांकि संबंधित के तहत नियम आजीवन कारावास की सजा के बराबर है 20 वर्ष की निश्चित अवधि में ऐसे कैदी को बिना शर्त रिहा किए जाने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है। ऐसी विशेष अवधि की समाप्ति, जिसमें

छूट भी शामिल है और केवल छूट पर काम करने के उद्देश्य से है कि उक्त वाक्य निश्चित अवधि के बराबर है न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।
(जोर दिया गया)

91. पंडित किशोरी लाल में वर्णित कानूनी स्थिति,गोपाल विनायक गोडसे, मारू राम, रतन सिंह और श्री भगवान और अस्वास्थ्यकर तरीका जिसमें माफी है वास्तव में आजीवन कारावास के मामलों में अनुमति दी जाती है के लिए एक विशेष श्रेणी बनाने के लिए बहुत मजबूत मामला कुछ मामले जहां मृत्युदंड को प्रतिस्थापित किया जा सकता है आजीवन कारावास या कारावास की सजा द्वारा चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और यह कहना कि छूट के अनुप्रयोग से परे की श्रेणी।

92. इस मामले को थोड़ा अलग तरीके से देखा जा सकता है। कोण। सजा सुनाने के मुद्दे के दो पहलू हैं। ए. सजा अत्यधिक और अनुचित रूप से कठोर हो सकती है या यह अत्यधिक असमान रूप से अपर्याप्त हो सकती है। जब कोई अपीलार्थी 12 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट देता है [2013] 2 एस सी आर। निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा लेकर इस अदालत में आता है और उच्च

न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, यह न्यायालय, जैसा कि वर्तमान अपील में पाया जा सकता है कि मामला दुर्लभतम श्रेणी से कम है और महसूस कर सकता है मौत की सजा का समर्थन करने में कुछ अनिच्छुक। लेकिन साथ ही, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि आजीवन कारावास की सजा छूट के अधीन कारावास आम तौर पर काम करता है 14 साल की अवधि अत्यधिक असमान और अपर्याप्त होगी। फिर अदालत को क्या करना चाहिए? अगर अदालत ने कारावास, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, अधिक नहीं 14 वर्ष से अधिक और दूसरी मृत्यु, न्यायालय महसूस कर सकता हैलुभाया जाता है और खुद को मौत की सजा का समर्थन करने के लिए प्रेरित पाता है। इस तरह का रास्ता वास्तव में विनाशकारी होगा। एक दूर।अधिक न्यायपूर्ण, उचित और उचित मार्ग होगा विकल्पों का विस्तार करना और उन चीज़ों को संभालना जो वास्तव में, कानूनी रूप से न्यायालय से संबंधित हैं, यानी विशाल अंतराल 14 साल की कैद और मृत्यु के बीच। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि न्यायालय इसका सहारा लेगा विस्तारित

विकल्प मुख्य रूप से क्योंकि मामले के तथ्यों में, 14 साल के कारावास की सजा किसी भी सजा के बराबर नहीं होगी।

93. इसके अलावा, सजा की एक विशेष श्रेणी का औपचारिकरण, हालांकि बहुत कम मामलों के लिए, मृत्युदंड होने का बड़ा लाभ होगा कानून की पुस्तक पर लेकिन वास्तव में इसका उपयोग जितना संभव हो उतना कम करने के लिए, वास्तव में दुर्लभतम मामलों में। यह केवल संविधान पीठ के फैसले की पुनः पुष्टि होगी। बचन सिंह पेनोलॉजी में आधुनिक रुझानों के अनुरूप होने के अलावा।

94. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इसका एक अच्छा और मजबूत आधार है न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास या चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मृत्युदंड की सजा को प्रतिस्थापित करने के लिए और साहिब हुसैन साहिब जान बनाम का राज्य राजस्थान [पी. सतशिवम, जे. जे.आगे यह निर्देश देने के लिए कि दोषी को उसके शेष जीवन के लिए या वास्तविक अवधि के लिए जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए

95. अंत में, हम सिन्हा, जे. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। हम तदनुसार दी गई मौत की सजा को प्रतिस्थापित करते हैं। निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी और उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास द्वारा पुष्टि की गई और निर्देश दिया कि वह नहीं करेगा जीवन भर जेल से रिहा रहें।

30. यह स्पष्ट है कि स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में, यह न्यायालय ने जगमोहन में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट किया सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1973) 1 एस. सी. सी. 20 और 5 साल बाद जगमोहन के मामले में निर्णय, धारा 433-ए को जोड़ा गया था। छूट की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाली संहिता में या कुछ मामलों में परिवर्त्तन। धारा 433 के लागू होने के बाद-इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684, धारा 433-ए के संबंध में शक्ति के संदर्भ में, जो धारा 433-ए को प्रदत्त छूट और परिवर्तन की शक्ति को प्रतिबंधित करती है। उपयुक्त सरकार ने जेल अधिनियम, जेल नियमावली आदि के विभिन्न प्रावधानों को नोट किया और निष्कर्ष निकाला कि उचित और उचित पाठ्यक्रम 14 वर्षों के बीच विकल्प का विस्तार करना होगा। कारावास और मृत्यु। बड़ी बेंच में भी है14 साल के कारावास की सजा नहीं होगी। सजा बिल्कुल भी "। वृहद पीठ द्वारा की गई विस्तृत चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि टिप्पणियाँ की

गईं संगीत के मामले में (ऊपर) वारंट नहीं हैं। अन्यथा भी, उपरोक्त सिद्धांत, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद में वर्णित है।(उपर्युक्त) केवल तभी लागू होते हैं जब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है और उन सभी मामलों में नहीं जहां न्यायालय आजीवन कारावास की सजा देता है।

31. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से अपराध को स्थापित किया है, विश्लेषण किया गया और पहले चर्चा की गई, और इस तथ्य के बारे में कि मामले में [2013] 2 एस. सी. आर. 1044 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और यह भी कि उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया कुछ प्रतिबंधों के साथ, उच्च न्यायालय के निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता है और एक पर अच्छी तरह से तर्कपूर्ण निर्णयों के प्रकाश में दशक, हम उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष से सहमत हैं, जिसमें उसमें बताए गए कारण भी शामिल हैं।

32. नतीजतन, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

33. हम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं विद्वान न्यायमित्र और राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत। याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री कुलदीप मस्तान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****